IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Annu Mahala

Assistant Professor in sociology

MGSU

शोध सार.

भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो और अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हो तो उस देश की सरकार का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह किसानों की उन्नति पर विशेष ध्यान दें। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में किसान अनेक समस्याओं यथा . अशिक्षाए अज्ञानताए अंधविश्वासए सामाजिक कुरीतियांए आत्महत्याए ऋणग्रस्तताए मानसून की विफलताए इनपुट लागत में वृद्धि आदि समस्याओं से जूझ रहे है। किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आधुनिकीकरणए पश्चिमीकरण एवं वैश्वीकरण के साथ.साथ कृषि ऋण व्यवस्थाए कृषि विपणन व्यवस्थाए सतत कृषि विकासए योजनाबद्ध तरीकों से विभिन्न योजनाओं को लागू करना जरूरी है । इसके लिएकिसानों का साक्षर होना एक आवश्यक शर्त है इस कार्य के लिए विभिन्न प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजनए दूरदर्शन व एफएम रेडियो और निजी चैनलों पर कृषि संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारणए किसान कॉल सेंटर के माध्यम से किसानों की विभिन्न समस्याओं का निवारण एवं प्रगतिशील किसानो के लिए कृषि भ्रमण यात्रा के साथ ही उन्नत कृषि यंत्र एवं मशीनीकरण के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना और किसानों को डिजिटल खेती के माध्यम से दूसरे किसानों के साथ जोड़ना आवश्यक है ताकि एक मंच पर कृषि से संबंधित जानकारियों को प्राप्त कर सके। कोविड में उद्योग धंधे बंद हो गए इसी क्षेत्र ने मजदूरए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया तथा कृषि से प्राप्त उत्पादन से राष्ट्र आत्मनिर्भर बनाया। जिससे कृषक वर्ग की न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि यह वर्ग कृषि के बहुमुखी विकास के माध्यम से एक राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाकर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत क्रांतिकारी परिवर्तनों को प्रोत्साहित कर सकेगा परिणामतः सामाजिक और आर्थिक मूल्य के प्रति अग्रेषित होंगे परिणामतः हमारी कृषि भरण. पोषण के उद्देश्य की बजाय आत्मनिर्भर कृषि के स्वरूप से ओतप्रोत होगी। देश की कृषि के क्षेत्र में हुए नव

परिवर्तन आर्थिक और सामाजिक जीवन के नवाचारों को प्रोत्साहित करके कृषि के क्षेत्र में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के सरोकारों को मूर्त रूप प्रदान करेंगे कृषि का सुदृढ़ीकरण अर्थव्यवस्था में परंपरागत दृष्टिकोण के स्थान पर आधुनिक कृषि कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का एक मुख्य आधार माना जाता है।किसान हमारे देश की ष्रीड की हड्डीष् के समान है इसलिए इनके प्रत्येक स्तर सामाजिकए आर्थिकए धार्मिकए राजनीतिकए और सांस्कृतिक को ऊंचा उठाना जरूरी है। किसानों को कर्ज माफी की नहीं बल्कि एक नियमित आय की आवश्यकता है तभी उनकी सामाजिकार्थिक स्थिति सुधर सकती है। आधुनिकीकरणए पश्चिमीकरण एवं वैश्वीकरण से शिक्षा व तकनीकी ज्ञान का प्रसार हुआ है और किसानों के जीवन में आशातीत परिवर्तन हुआ हैए विकास व परिवर्तन के संबंध में प्रमुख पहलू सामाजिकए आर्थिकए धार्मिक एवं सांस्कृतिक हैए इन सभी मे विकास व परिवर्तन गति समान अवस्था में नहीं पाई गईए जहां परंपरागत खेती के तरीकों में परिवर्तन व विकास की गति तीव्र है वहीं सामाजिकए सांस्कृतिक व धार्मिक पहलुओं में विकास और परिवर्तन की गति धीमी है। सामाजिक संस्थाओं जैसे. परिवारए जातिए विवाह में परिवर्तन की गति धीरे है क्यों कि अब भी किसानों में अज्ञानता व अंधविश्वास आदि पाया जाता हैए वहीं आर्थिक पहलु मे नई तकनीकी ज्ञानए मशीनीकरणए यंत्रीकरण एवं शिक्षा के कारण विकास व परिवर्तन की गति तीव्र है।

मुख्य शब्द रू आधुनिकीरणए पश्चिमीकरणए वैश्वीकरणए सामाजिक संस्थाए डिजिटल खेतीए ट्रैक्टरए मशीनीकरणए ट्यूबवेलए हाइब्रिड बीजए रासायनिक उर्वरक।

<u>परिचय</u>. वैश्वीकरण कृषि की भूमिका को बहुत कम आय वाले देशों में विकास के एक इंजन के रूप में बढ़ा सकता हैए जिससे कृषि के लिए घरेलू खपत में काफी तेजी से वृद्धि संभव है। यह कृषि के लिए व्यापक मल्टीप्लायरों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने परए रोजगार.गहनए गैर. पारंपरिक ग्रामीण गैर.कृषि क्षेत्र में वृद्धि की संभावना भी बढ़ाता है। ऐसे संभावित लाभों के साथए यह समझना महत्वपूर्ण है कि भागीदारी के लिए क्या आवश्यक है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन प्रक्रियाओं द्वारा गरीबों और भूखों को गरीबी और भूख से बाहर निकाला जाए।;1द्ध

किसान ही भारत का 'अन्नदाता', ष्माटी का लालष् और ष्धरतीपुत्रष् है। यदि हमें भारत को उन्नतशील और सबल राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना होगाए इसलिए किसानों से जुड़ा कोई भी अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किसान की परिभाषा से लेकर उसकी सामाजिकए आर्थिकए राजनीतिकए सांस्कृतिकए धार्मिक और जीवन स्तर के सभी पहलुओं पर गहराई से अध्ययन जरूरी है ताकि हम जान पाएंगे कि किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और हम उन्हें दूर करने के उपाय सुझा पाएंगे। भारतीय किसान का जीवन ष्करुणा का महासागरष् है वह स्वयं उपजाने के बाद भी उसे तथा उसके परिवार को भरपे खाने को नहीं मिलता। किसान के लिए ष्कृषि एक जुआष् है क्योंकि यहां अधिकांश सिंचाई के साधनों के अभाव में उसे मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है।

कृषक समाज की अवधारणा को सर्वप्रथम रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक श्पीजेंट सोसायटी एंड कल्चरश में परिभाषित करते हुए कहा है कि श्वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीकों का एक भाग है और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार का है।श

रॉबर्ट रेडफील्ड ने स्वीकार किया कि श्कृषकश शब्द को परिभाषित करना कठिन हैए रेडफील्ड के अनुसार कृषक वह है जो अपने उपयोग के लिए कृषि करता हैए न कि व्यापार के लिए जो व्यापार के लिए कृषि करता है उसे श्किसानश ;फार्मरद्ध कहते हैं।;2द्ध

अध्ययन स्रोतरू.

प्रस्तुत शोध पत्र में सम्मन संकलन एवं विश्लेषण के लिए द्वितीय स्रोतों का मुख्ता उपयोग लेना उचित समझा गया है जिसके पूर्व में प्रकाशित विषय से संबंधित पुस्तकों शोध पत्रों पत्र पत्रिकाओं केंद्र एवं राज्य सरकारों के अध्ययन कृषि विभागों द्वारा प्रकाशित सूचनाओं समाचार पत्रों के संपादकीय उद्बोधनों को आधार बनाया गया है ।

शोध साहित्य का पुनरावलोकनरू.प्रस्तुत शोध लेख में भारतीय कृषि क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को वैश्वीकरण से जोड़ने का प्रयास किया गया है अर्थात भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को को मूल्यांकन करने के लिए इस शोध लेख से संबंधित पूर्व में विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत शोध लेखों को विश्लेषण का आधार बनाया गया है।

पेपर के उद्देश्यरू.

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि व्यवस्था में सुधारो की संभावनाओं को खोजने रखा गया है इस आधारभूत उद्देश्य के साथ.साथ निम्नलिखित उद्देश्य भी इस शोध कार्य हेतु संयोजित किए गए हैं।

1Û भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना।

2Û सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की क्रियान्वित के परिणाम स्वरुप कृषि क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना।

3Û भारतीय कृषक वर्ग की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का बदलते परिवेश में अध्ययन करना।

4Û विश्व स्तर पर कृषि के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को भारतीय कृषि में हो रहे नवाचारों से अंतर संबंध करना।

1Û भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करनारू.

कृषि अब सकल घरेलू उत्पाद में केवल 15: का योगदान करती है। विश्व व्यापार संगठन और अन्य बहुपक्षीय संगठनों द्वारा लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों ने कृषि के लिए सरकारी समर्थन को कम कर दिया है। वैश्विक कमोडिटी बाजारों के अधिक एकीकरण से कीमतों में निरंतर उतार.चढ़ाव व होता है। इससे भारतीय किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले बीजों और उर्वरकों पर भी निर्भर हो रहे हैं।

वर्तमान में औद्योगिकरण की दौड़ के कारण उद्योगों के विकास और सड़क निर्माणए बांध निर्माण आदि में बहुतबार उपजाऊ भूमि का भी उपयोग किया जाता है। जिसके कारण कृषि क्षेत्र में कमी आ रही है तथा पानी की अनुपलब्धता एवं जमीन की उर्वरक क्षमता में कमी के कारण भी कृषि क्षेत्र में कमी आ रही हैं।

वैश्वीकरण का कृषि पर केवल सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीतए इसके कुछ हानिकारक प्रभाव होते हैं क्योंकि सरकार हमेशा खाद्यान्नए चीनी आदि आयात करने के लिए तैयार रहती है। जब भी इन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है।

सरकार कभी भी किसानों को अधिक भुगतान करने के बारे में नहीं सोचती है ताकि वे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करें लेकिन आयात का सहारा लें। दूसरी ओरए सब्सिडी कम हो रही है इसलिए उत्पादन की लागत बढ़ रही है। यहां तक कि उर्वरकों का उत्पादन करने वाले खेतों को भी आयात के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। जीएम फसलोंए शाकनाशी प्रतिरोधी फसलों आदि की शुरूआत जैसे खतरे भी हैं। ;3द्ध

2ण सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की क्रियान्वित के परिणाम स्वरुप कृषि क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करनारू.पहली पंचवर्षीय पूर्णतया कृषि केंद्रित थी। केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं लागू की गई है एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रयास किया गया।जिससे कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले तथा देश कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सके। भारतीय सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजनाएकेंद्रीय क्षेत्रक योजना एकृषि अवसंरचना कोष एमध्यम. दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा एराष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन आदि योजनाएं लागू की गई है जिससे कि कृषक वर्ग को सहायता प्राप्त हो।

राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमण एसण स्वामीनाथन अध्यक्षता में सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक श्किसान उस व्यक्ति को माना जाएगा जो कृषि वस्तुओं का उत्पादन करता है। इनके मुताबिक किसान की परिभाषा में सभी कृषकए कृषि मजदूरए बटाईदारए मुर्गीपालनए पशुपालनए मधुमक्खी पालनकर्ताए मालीए चरवाहेए गैर.कॉर्पोरेट बागान मालिक और रोपण मजदूरों के साथ.साथ कृषि संबंधित व्यवसाय जेसे सेरीकल्चरए वर्मीकल्चरए और कृषि वानिकी में लगे व्यक्ति शामिल है। इन शब्दों में आदिवासी परिवारए झूम खेती या स्थानांतरण कृषि और लघु एवं गैरवन उपज के संग्रहए उपयोग और बिक्री में शामिल लोग सम्मिलित हैं।श

भारतीय किसानों पर आधुनिकीकरणए पश्चिमीकरणए वैश्वीकरण के दोनों सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़े हैंए फिर भी कुल मिलाकर आधुनिकीकरणए पश्चिमीकरण और वैश्वीकरण से किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हुई है और उनके जीवन में परिवर्तन आया है। आधुनिकीरणए पश्चिमीकरण एवं वैश्वीकरण सभी प्रक्रियाओं का स्रोत बाहरी संस्कृति हैए उदाहरणार्थ दृ आधुनिकीकरण आधुनिक देशों के साथ संपर्क के परिणाम स्वरुप परंपरागत समाजों में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया हैए पश्चिमीकरण पश्चिमी संस्कृति के साथ संपर्क से होने वाले सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया हैए जबकि वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों से परस्पर संपर्क की परिणाम स्वरूप होने वाली परिवर्तनो से संबंधित प्रक्रिया है। इस के साथ ही संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिस का स्रोत भारतीय समाज में ही हैए संस्कृतिकरण में निम्न जाति या वर्ग द्वारा किसी उच्च जाती या वर्ग की जीवन शैली को अपनाया जाता है।; 4द्ध

3ण भारतीय कृषक वर्ग की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का बदलते परिवेश में अध्ययन करनारू.

विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के संचालन के साथ ए वैश्वीकरण की प्रक्रिया दुनिया के प्रमुख हिस्सों में शुरू हुई। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों और गैर.सदस्यों के बीच उनकी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर वैश्वीकरण के पेशेवरों और विपक्षों का आकलन करने में हमेशा भ्रम की स्थिति रही है। जिस क्षेत्र ने विश्व व्यापार संगठन के साथ.साथ विचारों और प्रतिवादों में सबसे अधिक विचार.विमर्श किया हैए वह कृषि हैए जो विकसित और विकासशील दुनिया के लिए समान रूप से अत्यधिक चिंता का क्षेत्र है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। यह कहना बेहतर होगा कि यह विश्व के कुछ देशों में कृषि से संबंधित विश्व व्यापार संगठन के पक्षपाती प्रावधानों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व कर रहा है।

भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित हैं।

एद्ध सकारात्मक परिणाम

1द्ध आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों की उपलब्धतारू

कीटनाशकोंए शाकनाशियों और उर्वरकों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के साथ.साथ उच्च उपज वाली फसलों की नई नस्लों को खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए नियोजित किया गया था। इन प्रौद्योगिकियों में सिंचाई परियोजनाओंए कीटनाशकोंए सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरक और उस समय उपलब्ध पारंपरिकए विज्ञान.आधारित विधियों के माध्यम से विकसित उन्नत फसल किस्मों में आधुनिक कार्यान्वयन शामिल थे। उच्च उपज देने वाली किस्मों ;भ्लटेद्ध का उपयोग जैसे प्त8 एक अर्ध.बौनी चावल की किस्म है। पर्याप्त सिंचाईए कीटनाशकों और उर्वरकों की उपस्थिति में भ्लटे ने पारंपरिक किस्मों को बेहतर प्रदर्शन किया।

2द्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि:

भ्ल्ट तकनीक को अपनाने के कारण देश में खाद्यान्न के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। गेहूँ का उत्पादन और अन्य खाद्यान्नों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि खाद्यान्न उत्पादन में काफी वृद्धि हुई हैए लेकिन हरित क्रांति का मोटे अनाजए दालों और पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। संक्षेप मेंए हरित क्रांति के लाभों को सभी फसलों द्वारा समान रूप से साझा नहीं किया गया है।

हरित क्रांति ने उपज बढ़ाकर लाखो लोगों भूख से जान बचाई।हरित क्रांति से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।भारत खाद्यान्न आयात और दूसरे देश पर निर्भरता के जोखिम से दूर किया।भारत कुछ खाद्यान्न उत्पादन जैसे गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर हो गया।

3द्ध राष्ट्रीय आय की वृद्धि.

भारत की कृषि वस्तुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्राप्त करने से किसान के कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई है। नई तकनीकए नए बीजए नई कृषि पद्धतियों आदि ने कृषि उत्पाद को विकसित करने में मदद की। मौद्रिक दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी को सकल घरेलू उत्पाद ;2010.11द्ध के 14ण्2: तक बढ़ा दिया गया है।

4द्ध नए क्षेत्र रोजगार.

कृषि उत्पादों का निर्यात करते समय उत्पादों का वर्गीकरणए मानकीकरण और प्रसंस्करणए पैकिंग आदि करना आवश्यक है। इसलिएए एलपीजी के बाद कृषि संबद्ध उद्योगों ने पैकिंगए निर्यातए मानकीकरणए प्रसंस्करणए परिवहन और कोल्ड स्टोरेज आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पैदा किया है। कृषि पर निर्भर उद्योगों का भण्डारण किया जाता है और इससे रोजगार में वृद्धि होती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है जिसका कुल असंगठित श्रम शक्ति में 90: से अधिक हिस्सा है । कुल रोजगार में कृषि का हिस्सा 52ण्1: है

5द्ध व्यापार में हिस्सेदारी में वृद्धि.

विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के कारण सभी देशों को समान अवसर मिलते हैंए इसलिए कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होती है। विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसारए निर्यात ;वस्तुओं और सेवाओंद्ध में भारत की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है।

6द्ध कृषि निर्यात में वृद्धि .

भारतीय बाजारों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कृषि वस्तुओं की कीमतें अधिक हैं। यदि विकसित देशों ने अनुदान कम किया हैए तो उन्हें कीमतों में वृद्धि करनी होगी। तो भारतीय बाजार में निर्यात में वृद्धि होगी और यदि कीमतें बढ़ती हैंए तो लाभ होगा। कृषि उत्पाद अर्थव्यवस्था की कुल निर्यात आय का 10ण्23: हिस्सा हैए जबकि कृषि आयात कुल आयात का सिर्फ 2ण्74: है। वर्ष 2011.13 में कृषि निर्यात 33ण्54 अरब डॉलर था।

7द्ध गरीबी में कमी.

यह भी सच है कि वैश्वीकरण को आमतौर पर अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाने के रूप में देखा जाता हैए लेकिन यह गरीबी को सापेक्ष दृष्टि से देखने का मामला है। भारत की पूर्व चिंता गरीबी को दूर करना हैए जो मृत्यु से भी बदतर हैए और यदि भारत प्रयास करता हैए तो वैश्वीकरण इससे छुटकारा पाने की कुंजी हो सकता है। इसके अलावाए गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत 1993.94 में 36 प्रतिशत से 2011.12 में 21ण्9 प्रतिशत तक उत्तरोत्तर घट रहा है।

भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक परिणाम हैं। लेकिन जहां तक कि भारत जैसे विकासशील देश का संबंध हैए इसके नकारात्मक परिणाम अधिक प्रभावी साबित होते हैं। ये इस प्रकार हैं।

बीद्ध नकारात्मक परिणाम.

1ण शातिर कर्ज का जाल और किसानों की आत्महत्या.

उन सभी कारणों की जांच करने की आवश्यकता है जिनके कारण कृषि क्षेत्र में वर्तमान संकट पैदा हुआ है और उदारीकरण की नीतियों ने जो भूमिका निभाई है उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश राज्यविश्व बैंक के साथ पहले राज्य स्तरीय समझौते का नेतृत्व कियाए जिसने अपने राज्य उद्योग और सरकार में सुधारों की एक श्रृंखला के बदले में 830 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण लिया। इसने विश्व बैंक उदारीकरण नीतियों को बड़े उत्साह और उत्साह के साथ लागू किया है और जैसा कि परिणामस्वरूप राज्य में किसानों की आत्महत्या की दर में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ;एनएसएसओद्ध की रिपोर्ट 2005 इंगित करती है कि 2 में से 1 खेत परिवार कर्ज में है और गैर.उत्पादन उद्देश्यों के लिए केवल 10 प्रतिशत कर्ज लिया गया था। साथ हीए 32ण्7 प्रतिशत किसान अभी भी साहूकारों पर निर्भर हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है कि 1997.2005 के बीच 1ए56ए562 किसानों ने आत्महत्या की। उनमें से लगभग 60ः 4 प्रगतिशील राज्योंए महाराष्ट्रए आंध्र प्रदेशए कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हुए। कर्नाटक में 20 फीसदी से ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। इसलिए उदारीकरण का अनुभव महत्वपूर्ण है।

2ण मजदूरों का प्रवास .

भारतीय किसान के लिएए जो पहले से ही कम उत्पादकता और कटाई के बाद भंडारण सुविधाओं की कमी से लकवाग्रस्त हैए जिसके परिणामस्वरूप उपज और राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। यह केवल उदारीकृत आयात शुल्क के कारण आयात में कम टैरिफ के कारण है जो एक धमाके के रूप में आया था। घरेलू किसान अंतरराष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा को बर्दाश्त नहीं कर सकेए जिसके परिणामस्वरूप कृषि से अन्य औद्योगिक गतिविधियों में श्रमिकों का पलायन हुआ है।(5)

3. ग्रामीण किसानों की कम आय:

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ के अनुसार ए व्यापार समझौते अब कृषि वस्तुओं को छोड़कर अधिकांश सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। यह विकासशील देशों में उन किसानों की आय को कम करता है जिन्हें सब्सिडी नहीं मिलती है। और चूंकि विकासशील देशों के 70 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैंए इसका मतलब है कि विकासशील देशों की आय कम है। लेकिन जिस भी मानक का उपयोग किया जाता हैए आज की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था विकासशील देशों के लिए अनुचित है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को कम करना ;विश्व बैंक गरीबी का उपायद्धय विकासशील देशों में आधे से अधिक लोग इससे कम पर जीवन यापन करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विकासशील देश में एक गरीब व्यक्ति होने की तुलना में यूरोप में गाय होना बेहतर है।

भारत में 60: जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि पर यह दबाव दिन.ब.दिन बढ़ता जा रहा है। सीमांत भूमि के कारण भारतीय किसानों की उत्पादन लागत अधिक होने के साथ. साथ कृषि उपज की गुणवत्ता और मानकीकरण की बहुत अधिक उपेक्षा की जाती है। इसके साथ ही सब्सिडी और अनुदान में कटौती से कृषि क्षेत्र कमजोर हुआ है। इसके विपरीत विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुदान में कटौती से पहले विकसित देशों ने बड़े पैमाने पर अनुदान का वितरण किया था।

5द्ध उर्वरकों और कीटनाशकों की कीमतों में असामान्य वृद्धि.

वैश्वीकरण के तुरंत बाद भारतीय रुपये का 25: अवमूल्यन हो गया और भारतीय फसलें वैश्विक बाजार में बहुत सस्ती और आकर्षक हो गईंए जिसने भारतीय किसान को निर्यात के लिए प्रेरित किया और उन्हें पारंपरिक फसलों के मिश्रण से मिर्च जैसी निर्यात उन्मुख श्नकदी फसलोंश में स्थानान्तरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जैसे कपास और तंबाकू। इन्हें पारंपरिक फसलों की तुलना में कहीं अधिक कीटनाशकोंए उर्वरकों और पानी की आवश्यकता होती है। इसने स्वतः ही उर्वरक और कीटनाशक की कीमतों में 300: की वृद्धि की।;6द्ध

6द्ध बिजली की दरें भी बढ़ाई गई हैं.

उदारीकरण से पहलेए सब्सिडी वाली बिजली नीति ने किसानों को उत्पादन की लागत कम रखने में मदद की। बिजली की लागत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई जब किसानों ने नकदी फसलों की खेती की ओर रुख कियाए जिसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता थीए इसलिएए अधिक पानी के पंपों की आवश्यक्ता थी और बिजली की अधिक खपत थी। आंध्र प्रदेश परंपरागत रूप से सूखा प्रवण होने के कारणए स्थिति और भी खराब हो गई। तथ्य यह है कि भारत की खेती योग्य भूमि का केवल 39: ही सिंचित हैए जिससे नकदी फसलों की खेती काफी हद तक अव्यवहारिक हो जाती हैए लेकिन निर्यात उन्मुख उदारीकरण नीतियां और लाभ की तलाश में बीज कंपनियां किसानों को दीवार पर धकेलती रहती हैं।

7द्ध पर्यावरणीय हानि

वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण कृषि में तकनीकी एवं उर्वरक रासायनिक खादों का विकास तो हुआ लेकिन इससे पर्यावरण की अत्यधिक हानि हुई मृदा के उपजाऊ ओपन में कमी आई तथा व्यापारिक कृषि एवं अत्यधिक उत्पादन एवं प्रतिस्पर्धा के कारण अधिक सिंचाई के कारण भी मिट्टी की उर्वरता में कमी आई तथा इसके कारण रासायनिक खाद एवं उर्वरक वाले फल सब्जियां एवं अनाज से मानवीय स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा है इसके कारण मानव संकट उत्पन्न हुआ है;7द्ध

8द्ध कृषि रोजगार में गिरावट.

वैश्वीकरण के कारण भारत में भारत में तकनीक का विकास हुआए जिसके कारण भारतीय कृषकों की रोजगार में गिरावट आई क्योंकि श्रमिक किसानों की जगह मशीनों ने ले ली इसके कारण बहुत से कृषक मजदूर बेरोजगार हो गए।

सुझाव.

;1द्धण खेती व इससे सम्बद्ध सेक्टरों की महिलाओं समेत अन्य वर्करों को प्रशिक्षित करना भी इतना ही जरूरी है ताकि वे आधुनिक व सतत कृषि उत्पादन और मूल्यवर्धन गतिविधि में प्रभावी तौर पर हिस्सा ले सकें। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर निष्पक्ष और दायित्वशील उत्पादन और व्यापारिक मुद्दों के साथ जोड़ने की जरूरत है। घरेलू बाजारों के लिए भी ये करने की आवश्यकता है।

;2द्धण ये भी समझना जरूरी है कि कृषि में भौतिक गतिविधियां ही नहींए बल्कि इस पेशे से जुड़े लोगों की आजीविका मायने रखती हैए जो मानव केंद्रित व अर्थपूर्ण नीतियां बनाने में राह दिखाएगी। और आजीविका तथा कृषि व्यवस्था या वैल्यू चेन एप्रोच इस सेक्टर के साझेदारों मसलन किसानए वर्कर और अन्य की बेहतरी में मदद कर सकती है।

;3द्धण इसलिएए सभी को फायदा हो इसके लिए कृषि व्यवसाय वैल्यू चेन में आधुनिक और बड़े खिलाड़ियों की ताकत का लाभ उठाने के लिए एक वैश्विक बाजार के संदर्भ में छोटे उत्पादकों के हित की रक्षा को केंद्र और राज्य स्तरों पर नीति और इससे भी अधिक प्रभावी विनियमन की आवश्यकता हैए ताकि समावेशी और प्रभावी सतत कृषि विकास का प्रयास किया जा सके।;8द्ध

निष्कर्ष.

अतः कृषि क्षेत्र में मौजूदा और उभरती चुनौतियों और स्थिरता की समस्याओं से निपटने के लिए उत्पादए प्रक्रिया और संगठनात्मक नवाचारों के अलावा संस्थागत नवाचारों की आवश्यकता है जिन्हें अवसरों में बदला जा सकता है। भारतीय कृषि व्यवसाय भविष्य हैए जिसमें कृषि भी शामिल है। कृषि सेक्टर सुनहरा तभी होगाए जब कॉरपोरेट एजेंसियांए जो केवल पूरक की भूमिका निभा सकती हैंए पर निर्भरता की जगह पब्लिक संस्थाएं जैसे सहकारी संस्थाएं और फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनियां इसमें भाग लें।

निष्कर्ष के तौर कहा जा सकता है कि यदि हमें अपने खेतों से लगातार उत्पादन करना है तो हमे परंपरागत खेती व आधुनिक खेती के बीच समन्वय स्थापित करना होगाए हमें उर्वरकोए कीटनाशको का सीमित उपयोग कर जैविक खाद व गोबर खाद की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

संदर्भ सूची:-

1. https://www.theindianwire.com

2. Agarwal G.k.,Pandya s.s.- gramin samajshastra

3.https://www.civilsdaily.com

4. https://agricoop.nic.in.(राष्ट्रीय किसान नीति 2007)

5.journals.tplondon.com

6.Kumar parvesh,वैश्वीकरण और भारतीय कृषि पर इसका प्रभावए रिसर्च रिव्यू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मल्टीडिसीप्लिनरी

7.बहुगुणा सुन्दरलाल ,(2007) ,धरती की पुकार ।

8. https://www.downtoearth.org.in